

डूंगरपुर में कृषि महाविद्यालय का हुआ ऑनलाइन शुभारम्भ

जलवायु के अनुरूप कम पानी में अधिक उत्पादन वाली फसलों के लिए हो कार्य
कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए युवाओं को कृषि से जोड़े जाने के हों प्रयास

— श्री कलराज मिश्र, राज्यपाल

कृषि को प्राथमिकता में रखते कृषि का अलग बजट लाने का किया राज्य सरकार ने निर्णय

— श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

जयपुर, 22 सितम्बर। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा है कि कृषि शिक्षा के लिए कहीं कोई एक कॉलेज भी खुलता है तो वह युवाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अवसर प्रदान करने जैसा है। उन्होंने युवाओं को कृषि से अधिकाधिक जोड़े जाने के लिए कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने, कृषि शिक्षा के तहत सूचना-संचार तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देने, स्थानीय जलवायु के अनुरूप कम पानी में अधिक उत्पादन वाली फसलों की पहचान कर कृषि के लिए उनकी अनुशंसा करने का कार्य भी विश्वविद्यालय स्तर पर किए जाने पर जोर दिया।

राज्यपाल श्री मिश्र महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की संघटक इकाई के रूप में स्थापित कृषि महाविद्यालय, डूंगरपुर के शुभारम्भ अवसर पर बुधवार को राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे कृषि शिक्षा के दौरान ही युवाओं को एक उद्यमी के रूप में सफल होने के लिए तैयार करें। इसके लिए उद्यमिता, कौशल प्रशिक्षण की सुविधाओं से युवाओं को लाभान्वित करने के प्रयास बढ़ाने जाने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को कृषि के क्षेत्र में अपना नया 'स्टार्ट-अप' व्यवसाय शुरू करने के लिए कृषि शिक्षा के दौरान ही प्रेरित किया जाए।

कृषि के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण, भण्डारण, विपणन आदि के साथ फार्म टूरिज्म जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कृषि शिक्षा की इस समय की सबसे बड़ी जरूरत यह भी है कि युवा खेती में नवीन और आधुनिक रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। उन्होंने खेती को समयानुरूप आधुनिक करने के साथ ही कृषि सुधारों के लिए पारम्परिक कृषि की भारतीय पद्धतियों को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने वैदिक खेती की चक्रीय परती प्रणाली की चर्चा करते हुए कहा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने, कम पानी में अधिक फसल और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में ऐसे पारम्परिक तरीके बेहद कारगर हो सकते हैं।

श्री मिश्र ने कहा कि कृषि शिक्षा और अनुसंधान से जुड़े लोग कृषि वैज्ञानिक कहे जाते हैं परन्तु खेतों के असली कृषि वैज्ञानिक किसान हैं। उन्होंने ऐसे कृषि वैज्ञानिकों के परम्परागत ज्ञान को सहेजते हुए कृषि शिक्षा में गुणवत्ता के साथ ही शोध व कृषि प्रसार गतिविधियों में गुणात्मक सुधार करने के लिए भी निरंतर कार्य किए जाने पर जोर दिया।

राज्यपाल ने कृषि को वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप अधिक लाभदायक बनाए जाने और प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा ऐसे युवा किसानों की सफलता की कहानियां प्रकाश में लाने की आवश्यकता जताई जिन्होंने खेती के जरिए अपना और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने वर्चुअल रीयलिटी आधारित कृषक उपयोगी सूचनाओं के संकलन के लिए कृषि में सूचना और संचार तकनीक को बढ़ावा दिए जाने की भी आवश्यकता जताई।

राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा पेटेन्ट कार्य, रोबोटिक्स संबंधित नव-प्रवर्तन, 'मेवाड़ ऋतु' एप से मौसम भविष्यवाणी आदि कदमों की सराहना करते हुए कृषि क्षेत्र में विश्वविद्यालय को देश का उत्कृष्ट केन्द्र बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि कृषि क्षेत्र पर ग्रामीण आबादी की निर्भरता को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा गत दो वर्ष में 13 कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। आदिवासी क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय प्रारम्भ होने से यहां के छात्रों की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र की शैक्षिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए ही बांसवाड़ा में अभियांत्रिकी महाविद्यालय और गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय प्रारम्भ किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल श्री कलराज मिश्र प्रदेश में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए व्यक्तिगत रुचि लेकर प्रयास कर रहे हैं, जिससे इस दिशा में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि को प्राथमिकता पर रखते हुए राज्य सरकार ने कृषि का अलग बजट प्रस्तुत करने का निर्णय किया है और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कृषि प्रसंस्करण नीति-2019 और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की है। किसानों को खुद की कृषि प्रसंस्करण इकाई लगाने पर एक करोड़ रुपये तक अनुदान दिया जा रहा है।

श्री गहलोत ने कहा कि कृषि शिक्षा के जरिए किसानों को सुदृढ़ करने के लिए अधिकाधिक कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने किसान हित में कृषि शोध और अनुसंधान कार्यों का दायरा बढ़ाए जाने, खेती को समय की जरूरत के हिसाब से समृद्ध करने के लिए प्रसार शिक्षा के तहत किसान सूचना तंत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया।

कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार ही उत्पादन में वृद्धि की कुंजी हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरसों, बाजरा सहित कई फसलों के उत्पादन में देशभर में अग्रणी है। दुग्ध उत्पादन में भी राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि पशुधन की नस्लों को लेकर भी राजस्थान की अपनी विशिष्ट पहचान है।

कृषि एवं पशुपालन राज्य मंत्री श्री भजनलाल जाटव ने कहा कि कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए राजस्थान में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय जिले डूंगरपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति डॉ. नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने अपने स्वागत उद्बोधन में विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना काल में संचालित की गई ऑनलाइन शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर गतिविधियों की जानकारी दी।

कार्यक्रम के आरम्भ में राज्यपाल श्री मिश्र ने उपस्थित जनों को संविधान की उद्देश्यिका एवं मूल कर्तव्यों का वाचन करवाया।

इस अवसर पर डूंगरपुर विधायक श्री गणेश घोघरा, कृषि, उद्यानिकी एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री दिनेश कुमार, राज्यपाल के सचिव श्री सुबीर कुमार, प्रमुख विशेषाधिकारी श्री गोविन्दराम जायसवाल, प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी, शिक्षक एवं विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित रहे।
